

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F-5(6)(139)/RCEE/CIVIL/2017-18/ 3355

दिनांक : 29/06/2017

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम/द्वितीय)
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग
जिला-समस्त

विषय :-बाढ़/अतिवृष्टि से बचाव के सम्बन्ध में

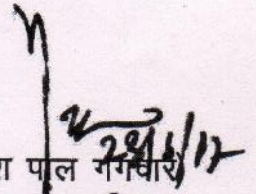
उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको विदित है कि मौसम विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जून के अंतिम सप्ताह में राजस्थान में मानसून आने की संभावित समयावधि घोषित की गई है।

मानसून अवधि के दौरान बाढ़/अतिवृष्टि से राजकीय विद्यालयों में नुकसान को न्यूनतम करने एवं क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत बाबत निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तथा प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावे, जिसमें 3 पारियों में 2-2 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जावे, 1 वरिष्ठ अधिकारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी नियुक्त किया जावे एवं 2 कार्मिकों को नियंत्रण कक्ष के नियमित कार्मिकों के अवकाश पर रहने की स्थिति के मद्देनजर आरक्षित रखा जावे। ब्लॉक स्तरीय नियंत्रण कक्ष के लैण्डलाईन नम्बर तथा नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं कार्मिकों के मोबाइल नम्बर जिला कार्यालय तथा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के लैण्डलाईन नम्बर तथा नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं कार्मिकों के मोबाइल नम्बर परिषद् को दिनांक 30.06.2017 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. संस्था प्रधान द्वारा राजकीय विद्यालय भवन परिसर में बाढ़/अतिवृष्टि से किसी भी की क्षति की सूचना 24 घण्टे के अन्दर एक साथ पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जावे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सूचना 8 घण्टे की अवधि के अन्दर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जावे तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सूचना 8 घण्टे की अवधि के अन्दर जिला कलेक्टर एवं परिषद् को उपलब्ध करायी जावे।
3. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त राजकीय विद्यालय भवनों की मरम्मत बाबत राज्य/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (प्रति संलग्न) के अनुरूप, इस बाबत विशेष रूप से गठित समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एफ.डी.आर./सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत वास्तविक क्षति के 3 दिवस के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत बाबत भी प्रस्ताव प्रेषित किये जावे। जिला कलेक्टर को प्रस्ताव प्रेषित करने के 3 दिवस की अवधि के अन्दर प्रेषित प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रपत्र में परिषद् को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

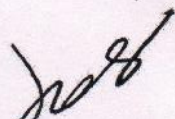
क्र.सं.	विद्यालय का नाम	आदर्श/ उत्कृष्ट/ अन्य	ग्राम पंचायत का नाम	ब्लॉक	विधानसभा क्षेत्र	क्षति की वास्तविक दिनांक	वर्षा की मात्रा (मिमी)	क्षति प्रकार/विवरण	मरम्मत हेतु अनुमानित लागत (रु. लाख)	जिला कलेक्टर को प्रस्ताव प्रेषित करने का क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4. असुरक्षित/जर्जर भवनों को अध्यापन या अन्य किसी उपयोग में नहीं लाया जावे, ताकि किसी भी प्रकार जान-माल की क्षति से बचा जा सके। अध्यापन बाबत स्वयं के स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
5. विद्यालय परिसर में बाढ/अतिवृष्टि के कारण एकत्रित जल का निकास 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग तथा 5वें राज्य वित्त आयोग के तहत कराने के लिए के लिए पंचायती राज विभाग/स्थानीय शहरी निकाय विभाग से सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा अनुरोध किया जावे।
6. वर्षा प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय भवन की छत, रेन वाटर पाईप, नालियों, परिसर इत्यादि की साफ-सफाई एवं लेवलिंग-ड्रेसिंग विद्यालय रख-रखाव अनुदान, विद्यालय सुविधा अनुदान, मामाशाह, जनसहयोग/क्राउड फण्डिंग, स्वैच्छिक विद्यालय विकास कोष के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा सुनिश्चित कराई जावे।


 (नरेश पाल गणेश)
 शासन सचिव
 दिनांक : 29/6/17

क्रमांक : F-5(6)(139)/RCEE/CIVIL/2017-18/ 3356
 प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान, जयपुर
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3. आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
8. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
9. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
10. उपायुक्त (आई.टी), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र को परिषद की वेबसाईट पर उपलोड कराना सुनिश्चित करे।
11. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
12. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
13. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग-समस्त
14. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग-समस्त
15. जिला प्रभारी अधिकारी (जिला-समस्त), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
16. जिला प्रभारी अधिकारी (जिला-समस्त), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
17. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, जिला-समस्त
18. जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला-समस्त
19. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, जिला-समस्त
20. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला-समस्त
21. सहायक अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान, जिला-समस्त
22. सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला-समस्त
23. कनिष्ठ अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
24. कनिष्ठ अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
25. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ब्लॉक-समस्त, जिला-समस्त
26. कनिष्ठ अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान, ब्लॉक-समस्त, जिला-समस्त
27. रक्षित पत्रावली


 (डॉ. जोगा राम)
 आयुक्त

No. 32-7/2014-NDM-I
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

'C' Wing, 3rd Floor, NDCC- II,
Jai Singh Road, New Delhi-110001,
Dated the 8th April 2015

To

1. Chief Secretaries of all States
2. The Relief Commissioners / Secretaries, Department of Disaster Management of all States

Subject: - Items and Norms of assistance from the State Disaster Response Fund (SDRF) and the National Disaster Response Fund (NDRF) for the period 2015 -- 2020.

Sir/ Madam,

I am directed to state that based on consideration of the recommendations of Fourteenth Finance Commission (FFC) on financing of expenditure on immediate relief during natural disasters for the period 2015--2020 and the report of the Expert Group set up by this Ministry, the Government of India has revised the items and norms for assistance from SDRF/NDRF. The approved list of items and norms for assistance from SDRF / NDRF in the wake of identified natural disasters is **Annexed**. The revised norms will be effective from 1st April 2015. However, the farmers affected by hailstorms in different parts of the country during February/ March 2015 will also be given assistance under the new norms.

2. The revised items and norms can also be downloaded from website of Disaster Management Division of Ministry of Home Affairs i.e. www.ndmindia.nic.in.

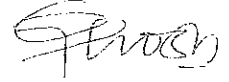
3. As the first charge on SDRF should be on a disaster of severe nature, there has been a requirement to adjust balance amount of SDRF whenever NDRF amount is released. This procedure stands revised as follows:-

50% of SDRF balance, as on 31st March of the preceding financial year, will be adjusted while releasing the assistance from NDRF for the first disaster in a financial year. In case the same State faces another severe disaster during the same year, no adjustment will be made while releasing NDRF assistance.

4. A copy of the communication alongwith their enclosure is also being sent to the Accountants Generals of the States for necessary action.

5. This supersedes this Ministry's earlier letters on this subject, the last being No.32-3/2013-NDM-I dated the 28th November, 2013 and No. 32-3/2013 NDM-I dated 5th March 2014.

Yours faithfully,



(Goutam Ghosh)

Deputy Secretary to the Govt. of India

Telefax: 23438123

Encl: As above.

Copy for information and necessary follow up action to:-

1. Accountants General of all State Governments.
2. Comptroller & Auditor General (CAG), New Delhi.
3. Controller General of Accounts (CGA), New Delhi.
4. Resident Commissioners of all State Governments.

Copy to: -

1. Ministry of Finance, Department of Expenditure [Shri Vivek Joshi, JS (FCD)], North Block, New Delhi.
2. Ministry of Agriculture [Joint Secretary (DM)], Krishi Bhawan, New Delhi.
3. Member Secretary, National Disaster Management Authority, NDMA Bhawan, Safdarjung Enclave, New Delhi.
4. All concerned Central Ministries/ Departments / Organizations.
5. PMO / Cabinet Secretariat.
6. PS to HM/ PS to MOS (R)
7. Sr. PPS to Home Secretary/ Addl. Secretary (F)/ Joint Secretary (DM)/ NIC.

www.rajteachers.com

REVISED LIST OF ITEMS AND NORMS OF ASSISTANCE FROM STATE DISASTER RESPONSE FUNDS (SDRF) AND NATIONAL DISASTER RESPONSE FUND (NDRF)

(Period 2015-20, MHA Letter No. 32-7/2014-NDM-I Dated 8th April 2015)

Sl. No.	Items	NORMS OF ASSISTANCE
1	2	3
1.	Gratuitous Relief	
	a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons.	Rs.4.00 lakh per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority.
	b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s).	Rs. 59100/- per person, when the disability is between 40% and 60%. Rs. 2.00 lakh per person, when the disability is more than 60%. Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability.
	c) Grievous injury requiring hospitalization	Rs. 12,700/- per person requiring hospitalization for more than a week. Rs. 4,300/- per person requiring hospitalization for less than a week.
	d) Clothing and utensils/ house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than two days due to a natural calamity.	Rs.1,800/- per family, for loss of clothing. Rs.2,000/- per family, for loss of utensils/ household goods.
	e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected.	Rs. 60/- per adult and Rs. 45/- per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise. Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year.
2.	SEARCH & RESCUE OPERATIONS	
	(a) Cost of search and rescue measures/ evacuation of people affected/ likely to be affected	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF).

		- By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/ near-actual costs.
	(b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives.	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.
3	RELIEF MEASURES	
	a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected/ evacuated and sheltered in relief camps.	As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM).
	b) Air dropping of essential supplies	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year.
4.	CLEARANCE OF AFFECTED AREAS	
	a) Clearance of debris in public areas.	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF.
	b) Draining off flood water in affected areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF).
	c) Disposal of dead bodies/ Carcasses	As per actuals, based on assessment of need by SEC and

		recommendation of the Central Team (in case of NDRF).
5	AGRICULTURE	
(i)	<i>Assistance farmers having landholding upto 2 ha</i>	
A.	Assistance for land and other loss	
	a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.)	Rs. 12,200/- per hectare for each item. (Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	Rs. 37,500/- per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.
B.	Input subsidy (where crop loss is 33% and above)	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	Rs. 6,800/- per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs. 13,500/- per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.1000 and restricted to sown areas.
	b) Perennial crops	Rs. 18,000/- ha. for all types of perennial crops subject to minimum assistance not less than Rs. 2000/- and restricted to sown areas.
	c) Sericulture	Rs. 4,800/- per ha. for Eri, Mulberry, Tussar Rs. 6,000/- per ha. for Muga.
(ii)	<i>Input subsidy to farmers having more than 2 Ha of landholding</i>	Rs. 6,800/- per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs.13,500/- per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas. Rs. 18,000/- per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas. Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer.
6	ANIMAL HUSBANDRY ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS	
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	<i>Milch animals -</i> Rs. 30,000/- Buffalo/ cow/ camel/ yak/ Mithun etc. Rs. 3,000/- Sheep/ Goat/ Pig <i>Draught animals -</i> Rs. 25000/- Camel/ horse/ bullock, etc. Rs. 16,000/- Calf/ Donkey/ Pony/ Mule - The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a

		<p>ceiling of 3 large milch animals or 30 small milch animals or 3 large draught animals or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government).</p> <p>Poultry:- Poultry @ 50/- per bird subject to a ceiling of assistance of Rs 5000/- per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity.</p> <p>Note:- Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.</p>
	ii) Provision of fodder / feed concentrate including water supply and medicines in cattle camps.	<p>Large animals- Rs. 70/- per day.</p> <p>Small animals- Rs. 35/- per day.</p> <p>Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year.</p> <p>Based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team, (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.</p>
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.
7	FISHERY	
	<p>i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Boat -- Dugout-Canoe -- Catamaran -- net <p>(This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)</p>	<p>Rs. 4,100/- for repair of partially damaged boats only</p> <p>Rs. 2,100/- for repair of partially damaged net</p> <p>Rs. 9,600/- for replacement of fully damaged boats</p> <p>Rs. 2,600/- for replacement of fully damaged net</p>
	ii) Input subsidy for fish seed farm	Rs. 8,200 per hectare.

		(This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.)
8	HANDICRAFTS/HANDLOOM ASSISTANCE TO ARTISANS	
	i) For replacement of damaged tools/ equipment	Rs. 4,100 per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	Rs. 4,100 per artisan for raw material. - Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
9	HOUSING	
	a) Fully damaged/ destroyed houses	
	i) Pucca house	
	ii) Kutch House	Rs. 95,100/- per house, in plain areas.
	b) Severely damaged houses	
	i) Pucca House	Rs. 1,01,900/- per house, in hilly areas including Integrated Action Plan (IAP) districts.
	ii) Kutch House	
	(c) Partially Damaged Houses –	
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is at least 15 %	Rs. 5,200/- per house
	(ii) Kutch (other than huts) where the damage is at least 15 %	Rs. 3,200/- per house
	d) Damaged / destroyed huts:	Rs. 4,100/- per hut, <i>(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutch house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)</i> <i>Note: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government.</i>
	e) Cattle shed attached with house	Rs. 2,100/- per shed.
10	INFRASTRUCTURE	
	<i>Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure:</i> <i>(1) Roads & bridges (2) Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community assets owned by Panchayat.</i>	<i>Activities of immediate nature :</i> Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed Appendix. <i>Assessment of requirements :</i> Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/

	<p>Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded.</p>	<p>schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).</p> <ul style="list-style-type: none"> - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are <ul style="list-style-type: none"> ◦ Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR). ◦ Hills: upto 20% of total of OR and PR. - In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for State Highway and Major District Road and @ Rs. 0.60 lakh/km for rural roads. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States. - In case of repairs of Bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh per damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the embankment portions, on par with the case of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes. - Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible damaged drinking water structures will be eligible for assistance @ Rs. 1.5 lakh/ damaged structure. - Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centres, Anganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs 2 lakh/damaged structure. - Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, poles and transformers upto the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer.
11	<p>Procurement of essential search, rescue and evacuation equipments including communication equipments, etc. for response to disaster.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). - The total expenditure on this item should not exceed 10 % of the annual allocation of the SDRF.

12.	Capacity Building	<ul style="list-style-type: none"> - Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.
13.	State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/ NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	<ul style="list-style-type: none"> - Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). - The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disasters, as listed above. or - In these cases, the scale of relief assistance against each item for 'local disaster' should not exceed the norms of SDRF. - The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters', with the approval of SEC.

Note:- (i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assistance is necessary/ mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojana etc.) of the beneficiary.

(ii) The scale of relief assistance against each items for all disasters including 'local disaster' should not exceed the norms of SDRF/ NDRF. Any amount spent by the State for such disasters over and above the ceiling would be borne out of the resources of the State Government and not from SDRF.

Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :

- i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/ spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.
- ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
- iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structure, approach gantries/jetties.

2. Roads

- i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
- ii) Repair of breached culverts.
- iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
- iv) Temporary repair of approaches to bridges/ embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation :

- i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.
- ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.
- iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.
- iv) Repair of embankments of minor, medium and major irrigation projects.

4. Health :

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/ community Health Centres.

5. Community assets of Panchayat

- a) Repair of village internal roads.
- b) Removal of debris from drainage/ sewerage lines.
- c) Repair of internal water supply lines.
- d) Repair of street lights.
- e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, *anganwadi*, etc.

6. Power: Poles/ conductors and transformers upto 11 kv.

7. The assistance will be considered as per the merit towards the following activities:

	Items/ Particulars	Norms of assistance will be adopted for immediate repair
i)	Damaged primary school building	Up to Rs. 1.50 lakh/ unit
	Higher secondary/ middle/ college and other educational institutions buildings	Not covered
ii)	Primary Health Centre	Upto Rs. 1.50 lakh/ unit
iii)	Electric poles and wires etc.	Normative cost (Upto Rs.4000 per pole and Rs. 0.50 lakh per km)
iv)	Panchayat Ghar/ Anganwadi/ Mahila Monda/ Yuva Kendra/ Community Hall	Upto 2.00 lakh/ unit
v)	State Highways/ Major District road	Rs. 1.00 lakh/ km *
vi)	Rural road/ bridge	Rs. 0.60 lakh/km *
vii)	Drinking water scheme	Upto 1.50 lakh/ unit
viii)	Irrigation Sector: Minor irrigation schemes/ Canal	Upto Rs. 1.50 lakh/ scheme
	Major irrigation scheme	Not covered
	Flood control and anti Erosion Protection work	Not covered
ix)	Hydro Power Project/ HT Distribution systems/ Transformers and sub stations	Not covered
x)	High Tension Lines (above 11 kv)	Not covered
xi)	State Govt Buildings viz. departmental/ office building, departmental/ residential quarters, religious structures, patwarkhana, Court premises, play ground, forest bungalow property and animal/ bird sanctuary etc.	Not covered
xii)	Long terms/ Permanent Restoration work incentive	Not covered
xiii)	Any new work of long term nature	Not covered
xiv)	Distribution of commodities	Not covered. (However, there is a provision for assistance as GR to families in dire need of assistance after a disasters).
xv)	Procurement if equipments/ machineries under NDRF	Not covered
xvi)	National Highways	Not covered (Since GOI born entire expenditure towards restoration works activities)
xvii)	Fodder seed to augment fodder production	Not covered

* If OR & PR rates are not provided by the State.

www.rajteachers.com